भगतसिंह जनअधिकार यात्रा

बेरोज़गारी, महँगाई, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता और जनता की लूट के ख़िलाफ़ !

रोज़गार, शिक्षा, चिकित्सा, आवास और जुझारू जनएकजुटता के लिए !

बढ़ती महँगाई की मार- ज़िम्मेदार मोदी सरकार!

सहयोग राशि: 10 रुपये

"बहुत हुई महँगाई की मार - अबकी बार मोदी सरकार"! इसी प्रकार के लोकलुभावन नारों के साथ भाजपा सरकार 2014 में सत्ता में आयी थी। अब कुछ नारों या जुमलों का नाम मोदी सरकार खुद ही नहीं लेती और अगर कोई उन्हें याद दिलाता है, तो उस पर देशद्रोह का मुक़दमा कर दिया जाता है! जैसे कि "अच्छे दिन", "बहुत हुई महँगाई की मार, बेरोज़गारी की मार अबकी बार मोदी सरकार", "बेटी बचाओ", आदि। इस आख़िरी वाले नारे के बारे में तो कुलदीप सेंगर, स्वामी चिन्मयानन्द, साक्षी महाराज, निहालचन्द मेघवाल, सन्दीप सिंह आदि जैसे भाजपा नेताओं के मामलों के सामने आने के बाद जनता को पता चला यह नारा नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी!

लेकिन 2014 में जनता परेशान थी, त्रस्त थी, श्रान्त-क्लान्त थी, इसलिए जुमलों पर भरोसा कर बैठी थी। यद्यपि, हमें कुछ ही दिनों में इन जुमलों की असलियत पता चल गयी। चाहे वह रोज़गार की बात हो, महँगाई की बात हो, शिक्षा व चिकित्सा की बात हो (कोरोना-काल में नदियों में बहती लाशों को कौन भूल सकता है?) या फिर महँगाई की बात हो, मोदी सरकार हर मोर्चे पर इस क़दर फ़ेल रही है जिस क़दर आज़ादी के बाद से कोई सरकार नहीं रही।

जनता के लिए महँगाई का मसला रोज़गार के साथ सबसे अहम मसला है। 2014 से पहले सामानों की क़ीमत और मोदी सरकार के कार्यकाल के बाद के सालों में सामानों की क़ीमत में ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ है। पिछले 9 सालों में जनता ने बेहिसाब महँगाई का सामना किया है। यूँ तो महँगाई की मार सबसे ज़्यादा मेहनतकश-मज़दूर आबादी पर पड़ी है लेकिन कोई भी तबका उससे अछूता नहीं रहा है। एक तरफ़ मेहनतकश जनता की आमदनी में कोई तब्दीली नहीं हो रही,

उल्टे वह घट रही है, और दूसरी तरफ़ महँगाई आसमान छू रही है। खाद्य पदार्थों से लेकर रसोई गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पेट्रोल उत्पादों के दाम बढ़ने से किराया-भाड़ा और हर अन्य वस्तु या सेवा का दाम भी बढ़ गया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी अपनी कमाई का **53 प्रतिशत** हिस्सा सिर्फ़ खाने पर ही ख़र्च कर देता है जबकि धनिकों की आय का मात्र **12 प्रतिशत** हिस्सा खाने पर ख़र्च होता है। आम मेहनतकश लोगों के भोजन की थाली से दाल, सब्ज़ी सब धीरे-धीरे करके ग़ायब होती जा रही है। **मोदी राज में 450 रुपये का गैस सिलिण्डर अब 1150 रुपये में, 55 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर में मिल रहा है।** यह सरासर झूठ है कि इस बढ़ोत्तरी की वजह अन्तरराष्ट्रीय बाज़ार में क़ीमतों की बढ़ोत्तरी है। 6 मार्च 2023 को अमेरिकी डॉलर में पेट्रोल की क़ीमत भारत में औसतन 1.269 डॉलर (104 भारतीय रुपये) प्रति लीटर थी, जबकि पाकिस्तान में यह 0.966 डॉलर (79.18 भारतीय रुपये) प्रति लीटर, इण्डोनेशिया में 0.91 डॉलर (74.59 भारतीय रुपये), अर्जेण्टीना में 0.938 डॉलर (76.88 भारतीय रुपये) प्रति लीटर, और युद्ध से तबाह अफ़गानिस्तान तक में 0.843 डॉलर (69.10 भारतीय रुपये) प्रति लीटर है।

वास्तव में, पेट्रोलियम उत्पादों की क़ीमतों में आधे से ज़्यादा हिस्सा तो सरकार द्वारा वसूला जाने वाला अप्रत्यक्ष टैक्स है। मोदी सरकार पेट्रोल और डीज़ल पर कितना कर वसूलती है, इसका एक उदाहरण देखिये। दिल्ली में पेट्रोल की आधार क़ीमत है रु. 34.19 रुपये। इसमें रु. 34.55 डीलर चार्ज, रु. 32.90 एक्साइज़ ड्यूटी, वैट रु. 21.36, डीलर कमीशन रु. 3.77 जुड़ता है और क़ीमत प्रति लीटर हो जाती है क़रीब रु. 97 प्रति लीटर। यह अन्यायपूर्ण अप्रत्यक्ष करों के ज़रिये लूट नहीं है तो और क्या है? पेट्रोल, डीज़ल, एलपीजी की क़ीमतों और नोटबन्दी, जी.एस.टी. की मार से आम जनता अभी कराह ही रही थी कि कोरोना काल में मोदी सरकार द्वारा थोपे गये अनियोजित लॉकडाउन ने जनता को अपनी चपेट में ले लिया। कोरोना में अनियोजित लॉकडाउन के कारण देश की स्थिति और बदतर हो गयी। इस दौरान सरकार द्वारा पूँजीपतियों को कर में खुली छूट और रियायतें मिलीं, लेकिन जनता के हिस्से आयी बेहिसाब महँगाई!

पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स लगाकर सरकार ने सबसे ज़्यादा धन बटोरा है और इसका इस्तेमाल पूँजीपतियों को टैक्स में छूट देने, नेताओं-मन्त्रियों और अफ़सरों की मोटी तनख़्वाहें और ऐय्याशी में ख़र्च किया है। सत्ता में बैठे हुक्मरानों की ऐय्याशी और पूँजीपतियों के मुनाफ़े की दर में कमी ना आये इसलिए जनता पर अप्रत्यक्ष करों का बोझ डाल दिया जाता है। महँगाई एक व्यवस्थाजनित परिघटना है परन्तु इसके असर को और फैलाने का काम मोदी सरकार अपनी नीतियों से कैसे कर रही है यह हम इस पुस्तिका में जानेंगे।

रिकॉर्डतोड़ महँगाई - आँकड़ों की ज़ुबानी

आठ साल बीतते-बीतते आख़िरकार नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता को "अच्छे दिन" दिखला ही दिये! थोक महँगाई दर मई 2022 में **15.08 प्रतिशत** पहुँच चुकी थी और इसी दौर में खुदरा महँगाई दर **7.8 प्रतिशत** पहुँच चुकी थी। 2023 में यह उम्मीद की जा रही थी कि यह कुछ कम होगी। लेकिन यदि बीते दो महीने की बात की जाये तो भारत में वार्षिक उपभोक्ता क़ीमत मुद्रास्फीति जनवरी 2023 में बढ़कर **6.52%** हो गयी, जो दिसम्बर में **5.72%** की तुलना में तीन महीनों में सबसे अधिक है। मुद्रास्फीति भारतीय रिज़र्व बैंक के **2-6%** के लक्ष्य से ऊपर चली गयी। बताते चलें कि भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए दो सूचकांकों का उपयोग किया जाता है - *उपभोक्ता क़ीमत सूचकांक (CPI)* और *थोक क़ीमत सूचकांक (WPI)*। सीपीआई, जो उपभोक्ता क़ीमत सूचकांक को सन्दर्भित करता है, 260 वस्तुओं व सेवाओं में खुदरा मुद्रास्फीति का विश्लेषण करता है। यह उन क़ीमतों के क़रीब बैठता है, जिन पर हमें चीज़ें दुकानों में मिलती हैं। थोक क़ीमतों का सूचकांक उत्पादन के स्थान पर थोक में होने वाली ख़रीद की दरों से तय होता है, जबकि खुदरा क़ीमतों का सूचकांक महँगाई की अपेक्षाकृत वास्तविक तस्वीर पेश करता है, यानी वे क़ीमतें जिन पर हम आम तौर पर बाज़ार में अपने ज़रूरत के सामान ख़रीदते हैं। सीपीआई यानी खुदरा क़ीमतों के सूचकांक से हम महँगाई की एक कमोबेश सटीक तस्वीर देख सकते हैं।

जनता के खाने-पीने की व बुनियादी ज़रूरत की वस्तुओं में आयी भारी महँगाई

जब मोदी जी ने साल 2014 में सत्ता संभाली, तब खुदरा मुद्रास्फीति औसतन 5.8 प्रतिशत थी। कच्चे तेल की कम क़ीमतों के चलते साल 2014 से 2019 तक महँगाई RBI के दायरे में रही, हालाँकि इस दायरे में रहने का यह अर्थ नहीं है कि आम जनता के लिए महँगाई कम थी। क्योंकि आम मेहनतकश जनता के लिए महँगाई का फ़ैसला केवल वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा क़ीमत से ही नहीं होता, बल्कि उनकी आमदनी से भी होता है। यह अब एक सर्वज्ञात तथ्य है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत में मालिकों, कम्पनियों, आदि के मुनाफ़े की दर को बनाये रखने के लिए आम मेहनतकश आबादी की आमदनी को ठहरावग्रस्त रखा गया है, या उसे डिप्रेस किया गया है। इसे 'इनकम डिप्रेशन' कहा जाता है, यानी आम लोगों की असल आमदनी को गिराना। बहरहाल, कोरोना महामारी के बाद 2020 में ऊपरी तौर पर रिज़र्व बैंक द्वारा तय सीमा में नज़र आ रही महँगाई 6 फ़ीसदी का आँकड़ा पार कर गयी। 2020 में औसत उपभोक्ता महँगाई 6.2 प्रतिशत थी। 2014 से 2023 की पूरी स्थिति आप नीचे दी गयी आलेख से देख सकते हैं।

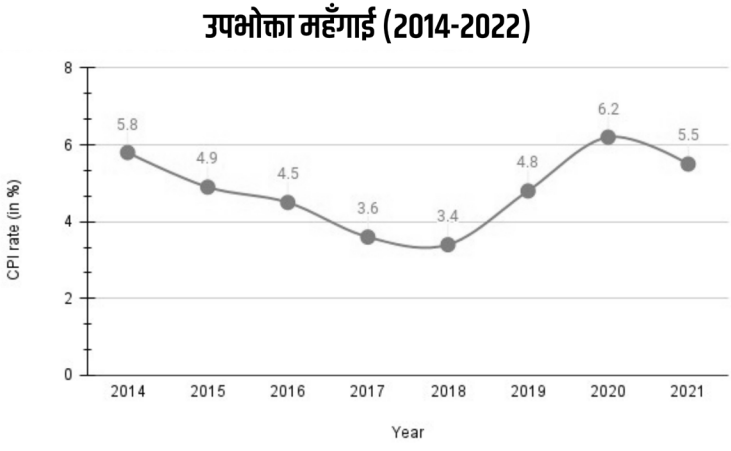

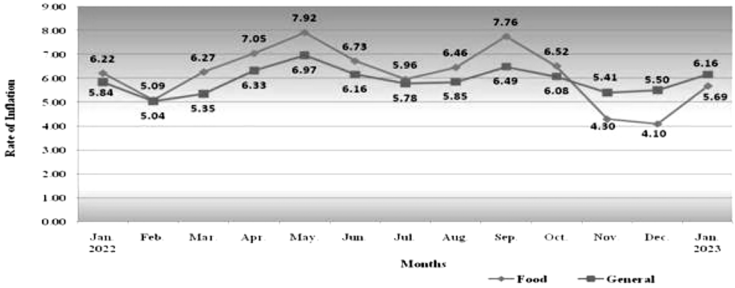

यदि पिछले तीन महीनों में खुदरा क़ीमत सूचकांक का विश्लेषण करें तो हम पायेंगे कि **अनाज (16.12%) और मसालों (21.09%) की सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज करने के साथ, खाद्य मुद्रास्फीति 4.19% से बढ़कर 5.94% हो गयी। आवास के लिए महँगाई दर भी तेजी से बढ़ी (4.62% बनाम 4.47%); पान, तम्बाकू और नशीले पदार्थ (3.07% बनाम 2.55%), और विविध (6.21% बनाम 6.17%) और ईंधन और प्रकाश (10.84% बनाम 10.97%) के लिए भी महँगाई दर ऊँची रही।** पिछले महीने की तुलना में, सीपीआई दिसम्बर में 0.45% की गिरावट के विपरीत, 0.46% बढ़ा।

इन आँकड़ों से आगे ज़रा ठोस तौर पर क़ीमतों पर आते हैं, जिससे एक साफ़ तस्वीर सामने आ सके कि मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण महँगाई ने आम आदमी की जेब पर किस क़दर डाका डाला है।

बढ़ते थोक व खुदरा क़ीमत सूचकांक का नतीजा यह है कि मई 2021 से मई 2022 के बीच ही **आटे की क़ीमत में 13 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी** हुई है। **दूध रु. 50/लीटर** व **वनस्पति तेल औसतन रु. 200/लीटर का आँकड़ा पार कर रहे हैं।** उस वक़्त **घरेलू रसोई गैस की क़ीमतों में 76 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी परन्तु अभी हाल में दुबारा से इसमें वृद्धि हुई है और सिलिण्डर का दाम रु. 1100 के पार जा चुका है। कॉमर्शियल रसोई गैस की क़ीमतों में 126 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है जो कि अब लगभग रु. 2400 पर बिक रहा है।** इसका अर्थ होगा आम तौर पर खाने-पीने के सामानों की क़ीमतों में भारी बढ़ोत्तरी। रसोई गैस की क़ीमतों में लगातार अन्यायपूर्ण बढ़ोत्तरी तो सीधे-सीधे ग़रीब मेहनतकश जनता के पेट पर लात मारने के समान है।

अगर हम **2017 से तुलना करें, तो चावल की क़ीमत में 24 प्रतिशत, गेहूँ की क़ीमत में 24 प्रतिशत, आटे की क़ीमत में 28 प्रतिशत, तूर/अरहर की क़ीमत में 21 प्रतिशत, मूँग की क़ीमत में 29 प्रतिशत और मसूर की क़ीमत में 32 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इसी प्रकार खाद्य तेलों में मूँगफली के तेल में 41 प्रतिशत, सरसो तेल में 71 प्रतिशत, वनस्पति तेल में 112 प्रतिशत, सोयाबीन तेल में 101 प्रतिशत, सूरजमुखी तेल में 107 प्रतिशत और पाम तेल में 128 प्रतिशत की क़ीमत बढ़ोत्तरी हुई है। सब्जियों में इन्हीं पाँच वर्षों में आलू में 65 प्रतिशत, प्याज़ में 69 प्रतिशत, टमाटर में 155 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि इन्हीं पाँच वर्षों में दूध की क़ीमत में 25 प्रतिशत, खुली चाय की क़ीमत में 41 प्रतिशत और नमक की क़ीमत में 28 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।** अब ज़रा तुलना करें कि 2017 से आपकी मज़दूरी/वेतन में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है। यदि यह भी 60 से 80 प्रतिशत तक नहीं है, तो इसका अर्थ है कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण हुई बढ़ोत्तरी के कारण आपकी वास्तविक आय कम हुई है और आप पहले से ग़रीब हुए हैं। देश के 80 फ़ीसदी मज़दूरों, ग़रीब किसानों, निम्न व मध्यम मध्य वर्ग की सच्चाई यही है: **यानी, पिछले 8 वर्षों में पहले की अपेक्षा वास्तविक आमदनी में कमी और उसकी ग़रीबी व बदहाली में बढ़ोत्तरी। वहीं दूसरी तरफ़ अडानियों, अम्बानियों, टाटाओं, बिड़लाओं, आदि यानी मोदी जी के दोस्तों की परिसम्पत्तियों में दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ोत्तरी हुई है।**

महँगाई का एक प्रमुख कारण: मोदी सरकार द्वारा विशेष तौर पर पेट्रोलियम उत्पादों पर व अन्य सभी उत्पादों पर अप्रत्यक्ष करों में की जा रही अन्यायपूर्ण बढ़ोत्तरी

मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान खाद्यान्न वस्तुओं और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में आयी वृद्धि को हम नीचे दिए गये ग्राफ़ से देख सकते हैं। इसके साथ ही 2014 से पहले और उसके बाद कुछ ज़रूरी खाद्यान्न वस्तुओं के दाम में आये बेतहाशा चढ़ाव को भी इंगित करने के लिए आप आख़िरी तालिका देख सकते हैं। जहाँ सिलिण्डर 450 रुपये में मिला करता था, वह अब 1100 रुपये हो चुका है। मोदी सरकार की 'उज्जवला योजना' की सच्चाई यह है कि आम ग़रीब मेहनतकशों के घर

में यदि सिलिण्डर पहुँच भी जाये तो वह ख़ाली पड़ा रहता है क्योंकि एक बड़ी मज़दूर आबादी के पास सिलिण्डर भरवाने का सामर्थ्य ही नहीं है।

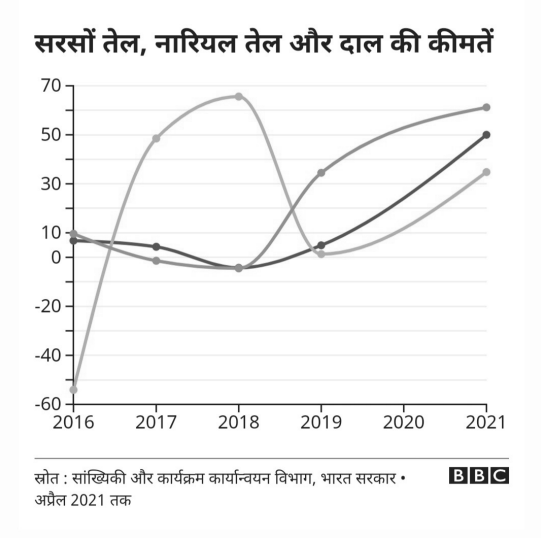

वस्तु	2014	2022
गैस सिलिण्डर	410	1050
पेट्रोल	70	100
डीज़ल	55	90
सरसों का तेल	90	200
दूध	35	60

पेट्रोलियम उत्पादों की बात करें तो पिछले **क़रीब आठ साल के अपने कार्यकाल में मोदी सरकार ने पेट्रोलियम के उत्पादों पर भारी कर लगाकार सरकारी ख़ज़ाने में क़रीब पच्चीस लाख करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की कमाई की है।** मोदी सरकार को आयात किया गया **कच्चा तेल बेहद सस्ते दामों पर** मिला है। डीलर को मिलने वाला हिस्सा ही पेट्रोल की क़ीमत का **36 प्रतिशत** ही होता है, जो कि सरकार ने पेट्रोल पम्प मालिकों, बिचौलियों आदि को

लाभ पहुँचाने के लिए ही रखा है। **ऊपर से, केन्द्र सरकार इस पर 37 प्रतिशत टैक्स वसूलती है और क़रीब 23 प्रतिशत वैट राज्य सरकारें लगाती हैं।** शेष 3-4 प्रतिशत डीलर का कमीशन, ढुलाई ख़र्च आदि होता है। **यानी ये सरकारों के टैक्स ही हैं जो पेट्रोल की क़ीमतों को 90 के पार (और कहीं-कहीं 100 के पार) पहुँचा दे रहे हैं।**

2013 तक पेट्रोल पर केन्द्र और राज्यों के टैक्स मिलाकर क़रीब 44 फ़ीसदी तक होता था, अब ये टैक्स 100-110 फ़ीसदी तक कर दिया गया है। आइये, मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल व डीज़ल पर की जा रही लूट को समझते हैं।

कच्चे तेल की क़ीमत	**68 डॉलर/बैरल**
159 लीटर कच्चे तेल की क़ीमत	**68 $**
1 लीटर कच्चे तेल की क़ीमत	**0.427 $ = 35.32 रुपये**
1 लीटर पेट्रोल के परिशोधन पर ख़र्च	**लगभग 3 रुपये**
उपयोग योग्य प्रति लीटर पेट्रोल पर सरकार का ख़र्च	**लगभग 38.32 रुपये**
जनता के लिए पेट्रोल की क़ीमत	**लगभग 100 रुपये**
प्रति लीटर पर असल क़ीमत से 156% ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है !	

आज अन्तरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमत 68 डॉलर प्रति बैरल है, यानी 159 लीटर की क़ीमत 68 डॉलर। यानी, प्रति लीटर पेट्रोल अन्तरराष्ट्रीय क़ीमत है 0.427 डॉलर। भारतीय रुपयों में प्रति लीटर कच्चे तेल की अन्तरराष्ट्रीय क़ीमत है मात्र 35.32 रुपये। कच्चे तेल के एक लीटर के परिशोधन (refining) का ख़र्च है लगभग 3 रुपये। यानी, उपयोग योग्य प्रति लीटर पेट्रोल पर सरकार को ख़र्च करने पड़ते हैं कुल लगभग 38.32 रुपये। लेकिन हमारे लिए पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर पर

पहुँच गया है। यानी, पेट्रोल की कुल क़ीमत में असल लागत केवल 38-29 रुपये के क़रीब है, जबकि आप दे रहे हैं 96 से 110 रुपये। यानी हर लीटर पर असल क़ीमत से 156% ज़्यादा तो आप सिर्फ़ टैक्स दे रहे हैं! दुनिया के किसी भी देश में शायद ही पेट्रोल पर इतना भारी टैक्स लगता हो। मसलन, तेल पर यूके में 61 फ़ीसदी, फ्रांस में 59 और यूएस में 21 फ़ीसदी टैक्स लगता है। यह डकैती नहीं तो क्या है कि माल की क़ीमत पर माल की क़ीमत से भी ज़्यादा टैक्स लगाकर जनता को बेचा जाय? मोदी जी ने ठीक ही कहा था: "धन्धा मेरे ख़ून में है, पैसा मेरे ख़ून में है!" (3 सितम्बर 2014, *डेकन क्रॉनिकल,* मोदी जी का बयान)।

यह साफ़ है कि देश में वित्तीय घाटे की भरपाई करने के लिए सरकार तेल पर भारी टैक्स लगा रही है। इस बार के बजट में पेट्रोलियम उत्पादों पर तो कुल सब्सिडी को रु. 9171 करोड़ से घटाकर रु. 2257 करोड़ कर दिया गया है। ज्ञात हो कि 2020-21 में यह रु. 37,000 करोड़ रुपये थी। सरकार के इन शुरुआती क़दमों से उसका यह इरादा साफ़ ज़ाहिर है कि आने वाले वक़्त में रसोई गैस से लेकर डीज़ल और पेट्रोल और महँगा होगा। **मोदी सरकार के राज में पेट्रोलियम उत्पादों पर भारी कर सरकार द्वारा जनता की लूट का एक प्रमुख ज़रिया है!**

आप पूछेंगे कि सरकार के वित्तीय घाटे का कारण क्या है? सरकार की आमदनी के प्रमुख स्रोत हैं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर। इसके अलावा, गैर-कर स्रोत आते हैं जिससे सरकार की कुल आमदनी का 20 प्रतिशत ही आता है। इसमें सरकारी उद्यमों से आने वाला मुनाफ़ा, ऋण पर ब्याज, विनियामक शुल्क आदि है। अन्य स्रोतों, जैसे कि सरकार बॉण्डों द्वारा लिये जाने वाले ऋण और उसके ब्याज को भी सरकारें अन्तत: कर लगाकर ही भरती हैं। **भारत में मुख्यत: आम मेहनतकश जनता द्वारा दिया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर, जिसमें जीएसटी,**

वैट, सरकारी एक्साइज़ शुल्क, आदि शामिल हैं, सरकारी खजाने का क़रीब 60 प्रतिशत बैठता है। यह वह टैक्स है जो सभी वस्तुओं व सेवाओं को ख़रीदने पर आप देते हैं, जिनके ऊपर ही लिखा रहता है 'सभी करों समेत'। इसके अलावा, सरकार बड़े मालिकों, धन्नासेठों, कम्पनियों आदि से प्रत्यक्ष कर लेती है, जो कि 1990 के दशक तक आमदनी का 50 प्रतिशत तक हुआ करता था, और जिसे अब घटाकर 30 प्रतिशत तक कर दिया गया है। **यह कॉरपोरेट और धन्नासेठों पर लगातार प्रत्यक्ष करों को घटाया जाना है, जिसके कारण सरकार को घाटा हो रहा है। दूसरी वजह है इन बड़ी-बड़ी कम्पनियों को टैक्स से छूट, फ्री बिजली, फ्री पानी, कौड़ियों के दाम ज़मीन दिया जाना, घाटा होने पर सरकारी ख़र्चों से इन्हें बचाया जाना और जनता के सरकारी बैंकों में जमा धन से इन्हें बेहद कम ब्याज दरों पर ऋण दिया जाना, उन ऋणों को भी माफ़ कर दिया जाना या बट्टे खाते में, यानी एनपीए (नॉन पफॉर्मिंग एसेट) बोलकर इन धन्नासेठों को फोकट में सौंप दिया जाना।** अब अमीरों को दी जाने वाली इन फोकट सौगातों से सरकारी ख़ज़ाने को जो नुक़सान होता है, उसकी भरपाई आपके और हमारे ऊपर टैक्सों का बोझ लाद कर मोदी सरकार कर रही है। **इसकी पहले की सरकारें भी यह करती रही हैं, लेकिन अमीरज़ादों के पायबोस और सिजदे करने के मामले में मोदी जी ने तो सबको ही शर्मिन्दा कर दिया है!**

ये जो कर लगातार बढ़ाये जा रहे हैं, इनका सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम उत्पादों पर कर बढ़ाकर किया जा रहा है। जो स्मृति ईरानी और मुटियाये-अघाये भाजपाई दुकानदार और नेता तेल व रसोई गैस की क़ीमतें बढ़ने पर ख़ाली सिलेण्डर, सब्ज़ी की माला लेकर सड़कों पर उछल-कूद कर रहे थे, वे आज ग़ायब हैं! क्यों? क्योंकि पहले की महँगाई राष्ट्रवादी नहीं थी, धर्म के ख़िलाफ़ थी, और मोदी जी जो महँगाई लाये हैं, वह राष्ट्रवादी महँगाई है जिसने धर्मध्वजा लहरा डाली है! इसी तरह की बेहूदा बातें करके आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। जितनी जल्दी आप समझ जायें उतना बेहतर है।

यह भी समझ लें कि जो लगातार कम होता प्रत्यक्ष कर बड़े-बड़े धन्नासेठ अपनी तिजोरियों से दे रहे हैं, उन तिजोरियों को भरने का काम भी अम्बानी-अडानी जैसों ने खुद मेहनत करके नहीं किया है। उसे भी आम मेहनतकश लोगों ने ही

अपनी मेहनत से भरा है। **धन अपने आप में कुछ नहीं, बल्कि किसी देश में पैदा होने वाले सभी उत्पादों (वस्तुओं व सेवाओं) के मूल्य का ही प्रतिबिम्बन है, उसकी अभिव्यक्ति है। सारे उत्पाद व सेवाएँ कौन पैदा करता है? वह मज़दूर, मेहनतकश व ग़रीब किसान, दफ़्तरों में जाने वाले निम्न व मध्यम मध्यवर्ग के लोग पैदा करते हैं, न कि तुंदियाये-खाए-अघाए-मुटियाए सेठ लोग!** आप कहेंगे कि 'लेकिन कारख़ाना व उत्पादन के अन्य साधन तो इन सेठों के हैं!' लेकिन साथियो, यहाँ दो बातों पर ग़ौर करिये: **पहली बात,** ये उत्पादन के साधन इनके पास आये कहाँ से? इन्हें भी तो मज़दूरों-मेहनतकशों ने ही बनाया है या फिर खान-खदान या ज़मीन के समान ये क़ुदरत की देन हैं, जिन पर हर इंसान का बराबर का हक़ है। बिल्कुल शुरुआत में खेत-खलिहान, खान-खदान व सभी उत्पादन के साधन भी जनता को अपनी राज्यसत्ताओं की मदद से ज़ोर-ज़बर्दस्ती कर इन अमीरों ने हमारे हाथों से छीना था, इसी के ज़रिये सारी ज़मीन और उत्पादन के साधन मुट्ठी भर अमीरज़ादों के हाथों में केन्द्रित हुए थे। आप प्राचीनकाल, मध्यकाल व आधुनिककाल का इतिहास पढ़ें, आपको ये सच्चाइयाँ पता चल जायेंगी। **दूसरी बात,** तमाम कारख़ाना मालिकों के कारखाने में लगे समस्त उत्पादन के साधनों की, यानी इमारत, मशीनें आदि, क़ीमत के बराबर मुनाफ़ा तो मज़दूर एक-दो साल में ही पैदा करके पूँजीपतियों को दे डालते हैं। उसके बाद, कायदन तो इस सारी सम्पदा पर मज़दूरों का साझा हक़ होना चाहिए।

इसलिए जिस मुनाफ़े के एक छोटे-से हिस्से को सारे सेठ, व्यापार, अमीरज़ादे प्रत्यक्ष कर के तौर पर देते हैं, वह भी जनता का ही धन है, इन धन्नासेठों के पप्पा-दद्दू लोगों ने नहीं पैदा किया। हम उनके लिए खटने को मजबूर होते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी मेहनत करने की क्षमता के अलावा कुछ नहीं है, हमारे सारे साधन, कुदरत पर हमारे साझे हक़ सदियों पहले लूटे और छीने जा चुके हैं और आज भी लूटे और छीने जा रहे हैं।

इसलिए, आज की एक प्रमुख माँग यह है कि सरकार सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करे, जो मुख्यत: आम मेहनतकश जनता देती है और जो महँगाई बढ़ाने का एक प्रमुख कारण हैं, क्योंकि समाज के लिए हर ज़रूरी चीज़, सुई से लेकर जहाज़ तक, बनाकर मेहनतकश आम जनता ने अपने लिए निशुल्क व समान शिक्षा, निशुल्क व समान चिकित्सा, सरकारी आवास, रोज़गार के हक़

और अन्य सभी बुनियादी ज़रूरतों की क़ीमतों को पहले ही चुका दिया है। अब उस पर अप्रत्यक्ष करों का बोझ बिल्कुल नहीं लादा जाना चाहिए। उत्पादक वर्ग जो खुद ही सबकुछ पैदा कर रहा है, वह चीज़ों को ख़रीदने के लिए सरकार को टैक्स क्यों दे? वह आपस में उनका विनिमय करने हेतु उनका दाम दे सकता है, लेकिन सरकारी नेताओं, मन्त्रियों की ऐय्याशी और पूँजीपतियों को फोकट की सौगातें देने के लिए वह अप्रत्यक्ष कर क्यों दे? सरकार को अपने ख़र्चों के लिए धन की आवश्यकता अवश्य होती है, लेकिन यह वह प्रत्यक्ष करों के द्वारा धनी वर्गों, कॉरपोरेटों, उच्च मध्यवर्ग आदि से कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, उत्तराधिकार कर आदि लेकर वसूले, यानी उन वर्गों से जो किसी ज़रूरी वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं करते, बस जोंकों की तरह समाज के शरीर पर चिपके हुए हैं और उसका ख़ून चूस रहे हैं।

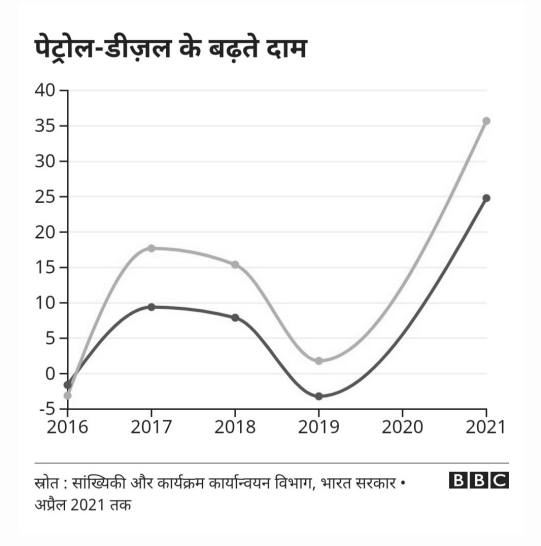

महँगाई कोई प्राकृतिक आपदा नहीं धन्नासेठों-अमीरज़ादों की मुनाफ़ाख़ोरी का नतीजा है!

साथियो, महँगाई कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है जिसे क़ाबू न किया जा सकता हो। असल में महँगाई मुनाफ़े पर आधारित इस पूँजीवादी व्यवस्था की नैसर्गिक पैदावार है। हमें यह समझना चाहिए कि महँगाई एक ऐसी व्यवस्था द्वारा पैदा होती है जिसके केन्द्र में पूँजीपति वर्ग का मुनाफ़ा होता है, न कि समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना। एक ऐसी व्यवस्था में समाज की समस्त आवश्यकताओं का कोई योजनाबद्ध आकलन करके उत्पादन, विनिमय व वितरण नहीं होता है। नतीजा होता है उत्पादन की अराजकता। यह अराजकता भी अलग-अलग समय पर अलग-अलग वस्तुओं और सेवाओं की क़ीमतों को बढ़ाती है। मौजूदा दौर में भी रिकॉर्डतोड़ महँगाई के पीछे यह समूचा पूँजीपति वर्ग, उसकी मुनाफ़ा-केन्द्रित व अराजक अर्थव्यवस्था और ऐसे आर्थिक सम्बन्धों की रक्षा करने वाली उसकी राज्यसत्ता खड़ी है। चन्द मुट्ठीभर पूँजीपतियों का मुनाफ़ा जारी रखा जा सके इसके लिए संकट के दौर में उसका बोझ आम मेहनतकश जनता पर डाला जाता है। मज़दूरी को तरह-तरह से कम करके पूँजीपतियों के मुनाफ़े की दर को क़ायम रखा जाता है। **यही महँगाई के आम बुनियादी कारण हैं।** पिछले डेढ़ दशकों से, मुनाफ़े की गिरती दर का संकट, जिससे पूरे विश्व की व्यवस्था जूझ रही है, वह और गहरा गया, जब कोरोना काल आया और उसके कारण थोपे गये कुप्रबन्धित लॉकडाउन की घोषणा हुई।

मुनाफ़े की अन्धी हवस ही असल में मुनाफ़े की गिरती औसत दर का कारण होता है। उत्पादन की प्रक्रिया ऐसी होती है कि लगातार प्रक्रिया में जीवित श्रम यानी मज़दूरी का हिस्सा सापेक्षतः कम होता जाता है और मृत श्रम (यानी मशीनें, कच्चा माल आदि) का हिस्सा बढ़ता जाता है, जो कि मुनाफ़े की औसत दर को अन्ततः गिराता है। जब मुनाफ़े की औसत दर गिरती है तो पूँजीपति वर्ग के निवेश की दर भी कम होती है क्योंकि यहाँ उत्पादन का मक़सद लोगों की ज़रूरत पूरी करना नहीं बल्कि मुनाफ़ा निचोड़ना होता है। ऐसे वक़्त में यह वर्ग उत्पादन में निवेश करने की बजाय सट्टेबाजी और शेयर बाज़ार में अपनी पूँजी खपाता है। निवेश की दर कम होने के साथ रोज़गार के दर में कमी होती है, मज़दूरों की रिज़र्व

सेना बढ़ती जाती है और इसी वजह से औसत मज़दूरी में कमी आती है और इसके साथ ही संकट के दौर में निवेश में कमी के साथ तमाम माल व सेवाओं की आपूर्ति भी माँग की तुलना में घट सकती है। औसत मज़दूरी के घटने के साथ भी आम मेहनतकश वर्ग के लिए महँगाई में बढ़ोत्तरी होती है, तब भी जबकि वस्तुओं व सेवाओं की क़ीमतों में कोई विशेष बढ़ोत्तरी न हो। लेकिन एक अराजक व्यवस्था में वास्तविक बाज़ार क़ीमतों में भी बढ़ोत्तरी आ सकती है। इस प्रकार मज़दूरों की वास्तविक मज़दूरी में कमी आती है और उनके लिए महँगाई की दर में बढ़ोत्तरी होती है।

एक पूँजीवादी व्यवस्था में महँगाई अन्य समस्याओं जैसे बेरोज़गारी, असमानता, मन्दी, ग़रीबी की तरह ही व्यवस्थाजनित है। लेकिन इसके साथ ही अभी के दौर में कमरतोड़ महँगाई के कुछ अन्य प्रमुख कारण भी मौजूद हैं। ख़ास तौर पर मोदी सरकार के कार्यकाल में महँगाई ने अपने पुराने सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिये और इसका कारण रहा मोदी सरकार की पूँजीपरस्त नीतियाँ को लागू करने का तानाशाहाना तरीक़ा जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कोरोना महामारी के वक़्त दुनिया के अधिकांश देशों में पूँजीपति वर्ग द्वारा थोपे गये अनियोजित किस्म के लॉकडाउन ने पूरी दुनिया में उत्पादन और सरकुलेशन की व्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित किया। इस कारण आपूर्ति श्रृंखला लगभग सभी क्षेत्रों में बाधित रहे और बाज़ार में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की माँग और आपूर्ति में भारी असन्तुलन पैदा हुआ, जिस कारण से उनकी क़ीमतें बढ़ने लगीं। लॉकडाउन के खुलने के साथ अचानक माँग में और भी वृद्धि आयी। वनस्पति तेलों की क़ीमतों में पिछले वर्ष आये जबरदस्त उछाल के पीछे का मूल कारण यही है। भारत की बात की जाये तो भारत अपने खाद्य तेल उपभोग के 60% से भी ज़्यादा के लिए आयात पर निर्भर है। नतीजतन, विश्व बाज़ार में क़ीमतों के उछाल का प्रभाव भारत में खाद्य तेलों की क़ीमत पर भी पड़ा। **कोरोना काल में सापेक्षिक माँग में अनपेक्षित बढ़ोतरी के कारण ना सिर्फ़ बड़े पूँजीपतियों-धन्नासेठों बल्कि व्यापारियों-बिचौलियों, धनी किसानों व कुलकों ने इस आपदा को अवसर में तब्दील किया और अपने मालों पर ऊँची क़ीमतें वसूल की जिन्हें वायदा व्यापार, जमाख़ोरी और सट्टेबाज़ी के ज़रिये सभी मुनाफ़ाखोरों ने और भी बढ़ाया। इसमें तिलहन उत्पादन धनी फार्मर, बिचौलिये-आढ़तिये, व्यापारी**

सभी शामिल थे, जो सट्टेबाज़ी और जमाख़ोरी के ज़रिये क़ीमतों को और भी बढा रहे थे। अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसका मक़सद लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना हो, तो ऐसी स्थिति ही पैदा नहीं होगी क्योंकि इस दौर में भी अधिकांश मालों का कृत्रिम अभाव पैदा किया जा रहा था, जिससे कि उनकी क़ीमतों को बढ़ाया जा सके। **वास्तव में, जमाख़ोरी और वायदा व्यापार के ज़रिये सट्टेबाज़ी कर मालिकों, धनी किसानों, बिचौलियों, आढ़तियों, व्यापारियों आदि द्वारा क़ीमतों को कृत्रिम रूप से अपनी मुनाफ़ाख़ोरी के लिए बढ़ाया जाना और कालाबाज़ारी हमारे देश में महँगाई का एक महत्वपूर्ण कारण है। यह सारा कुकर्म कभी भी सरकार की मौन सहमति व समर्थन के बिना हो ही नहीं सकता है।**

कोरोना के अलावा बुनियादी मालों की आपूर्ति श्रृंखला में बाधा **रूस-यूक्रेन युद्ध** द्वारा पैदा हुई। रूस तेल व प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश है और रूस से आपूर्ति के बाधित होने के कारण विश्व बाज़ार में तेल और प्राकृतिक गैस की क़ीमतों में उछाल आया है और इनकी क़ीमतों में उछाल आने के कारण अन्य उत्पादों की क़ीमतों में भी उछाल आया क्योंकि अन्य उत्पादों के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में तेल और प्राकृतिक गैस शामिल होते हैं और साथ ही परिवहन की पूरी व्यवस्था इन पर निर्भर करती है। इसके अलावा, रूस और यूक्रेन मिलकर दुनिया भर में गेहूँ की आपूर्ति के बड़े हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं। यूक्रेन सूरमुजखी और मक्के का भी भारी पैमाने पर निर्यात करता है। युद्ध ने विश्व बाज़ार में इन खाद्य मालों की आपूर्ति में भी भारी कमी लायी जिसके कारण इन बुनियादी मालों की क़ीमतों में भी भारी उछाल आया है। **इसके कारण, समूचा पूँजीपति वर्ग, यानी मालिक, कम्पनियाँ, व्यापारी, धनी किसान, दलाल, आढ़तिये, बिचौलिये, कमीशनख़ोर, आदि का समूचा वर्ग ही तमाम देशों में इसका फ़ायदा उठा रहा है। भारत में भी गेहूँ उत्पादन करने वाले पूँजीवादी कुलकों-फार्मरों ने लाभकारी मूल्य पर गेहूँ सरकारी मण्डी में बेचने की बजाय खुले बाज़ार में 30 से 40 प्रतिशत ऊपर क़ीमतों पर बेचा और भरपूर मुनाफ़ा कमाया।** खाद्यान्न के व्यापार व संसाधन में लगे बड़े पूँजीपति भी इसका पूरा फ़ायदा उठाने में लगे हुए हैं। गेहूँ व अन्य खाद्यान्न समेत सब्ज़ियों व खाद्य तेल की क़ीमतों में बढ़ोत्तरी की मार सीधे सबसे ग़रीब मेहनतकश आबादी पर पड़ रही है,

जिसके लिए सीधे तौर पर अमीरज़ादों व धन्नासेठों की पूरी जमात ज़िम्मेदार है, जिसके लिए पलक-पाँवड़े बिछाये मोदी सरकार बैठी है। क्योंकि इन्हीं के चन्दों से संघ परिवार व भाजपा के "राष्ट्रवाद" और "धर्मरक्षा" का बाज़ार चलता है।

महँगाई के अन्य प्रमुख कारणों में एक सबसे अहम कारण व्यापक मेहनतकश आबादी की औसत आय में कमी रही है जिस वजह से वास्तविक मज़दूरी में कमी आयी और विशेष तौर पर मेहनतकश जनता के लिए महँगाई बढ़ी। व्यापक मेहनतकश आबादी की औसत मज़दूरी को कम करने के लिए मोदी सरकार एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रही है और इसी वजह से बढ़ती महँगाई की मार सबसे ज़्यादा मेहनतकश आबादी को ही झेलनी पड़ रही है।

आम मेहनतकश आबादी की आय में गिरावट और महँगाई का प्रकोप

एक तरफ़ तमाम चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ़, आम मेहनतकश आबादी की आय में या तो गिरावट आयी है या फिर वह लगभग स्थिर है। इस कारण से आम आबादी की ख़रीदने की क्षमता पहले से कम हुई है। अभी हालत यह है कि एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अगर आप रु. **25,000** मासिक कमाते हैं तो आप भारत के ऊपरी **10** प्रतिशत आबादी में आते हैं! आपको बता दें कि उजरती श्रमिकों का **57** प्रतिशत भारत में रु. **10,000** मासिक से कम कमाता है और समस्त उजरती श्रमिकों की बात करें तो उनकी औसत आय रु. **16,000** मासिक है। निश्चित तौर पर, इसमें सबसे कम कमाने वाले मज़दूर वे हैं जो कि अनौपचारिक व असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और कुल मज़दूर आबादी का क़रीब **93 प्रतिशत** हिस्सा हैं। यानी, एक ओर महँगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं दूसरी ओर आम मेहनतकश आबादी की औसत आमदनी विशेष तौर पर कोविड महामारी के बाद से या तो ठहरावग्रस्त है या फिर घटी है। वित्तीय वर्ष **2021-22** के पहले नौ माह के दौरान ग्रामीण खेतिहर वास्तविक मज़दूरी में मात्र **1.6 प्रतिशत** की बढ़ोत्तरी हुई, जबकि ग्रामीण गैर-खेतिहर वास्तविक मज़दूरी में **1.2 प्रतिशत** की गिरावट आयी। भारत की राज्य सरकारों के कर्मचारियों की औसत वास्तविक आय में **2019** से **2021** के अन्त तक **6.3 प्रतिशत** की बढ़ोत्तरी हुई। इसी दौर में मनरेगा मज़दूरों की वास्तविक मज़दूरी में मात्र **4 प्रतिशत** की बढ़ोत्तरी हुई। इसके अलावा, स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध **2800**

कम्पनियों के कर्मचारियों की आय में **13 प्रतिशत** की बढ़ोत्तरी हुई, हालाँकि इसका बड़ा हिस्सा मध्यवर्गीय व उच्च मध्यवर्गीय कर्मचारियों के खाते में गया और आम मज़दूरों की मज़दूरी में बहुत ही कम बढ़ोत्तरी हुई है। **इसी बीच, महँगाई में 40 से 60 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी हुई, यानी इन सभी जमातों की असली आमदनी में कमी आयी और वह पहले से ग़रीब हुआ। सबसे बुरी हालत अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले मज़दूरों की रही।** कोविड महामारी के दौरान ही उनकी औसत मज़दूरी में बढ़ी बेरोज़गारी के कारण **22 प्रतिशत** की गिरावट आयी थी। ज़मीनी स्तर की सच्चाई तो इससे भी भयानक है। श्रम-मन्त्रालय के ही आँकड़ों के मुताबिक़ भारत में **45** फ़ीसदी मज़दूरों की मज़दूरी **10 हज़ार रुपए** से भी कम है, वहीं महिला मज़दूरों (कुल मज़दूर आबादी का **32 फ़ीसदी**) को **5 हज़ार रुपए** से भी कम मज़दूरी मिलती है। **ग्रामीण मज़दूरों की स्थिति और भी बुरी है।** चार्ट के मुताबिक़ भारत में कृषि क्षेत्र में औसत मज़दूरी की दर **344 रूपये प्रतिदिन** है। लेकिन सच्चाई यह है कि खेतों, भट्ठों, भवन निर्माण आदि में काम करने वाले मज़दूर प्रतिदिन **200-250 रुपये प्रतिदिन** के रेट से काम करने पर मजबूर हैं। **1984** में जहाँ कुल उत्पादन लागत का **45 प्रतिशत** हिस्सा मज़दूरी के रूप में दिया जाता था वो **2010** तक घटकर **25 प्रतिशत** रह गया। अब तो वह और भी घट चुका है।

संगठित क्षेत्र में पैदा होने वाले हर 10 रुपये में मज़दूर वर्ग को केवल 23 पैसा मिलता है। उसके ऊपर मोदी सरकार द्वारा रहे-सहे श्रम कानूनों को भी ख़त्म किया जा रहा है और उनके बदले चार लेबर कोड बनाये गये हैं, और न्यूनतम मज़दूरी को क़ानूनन तरीके से कम किया जा रहा है। सरकार के श्रममन्त्री प्रतिदिन के लिए तल-स्तरीय मज़दूरी **178 रुपये** करने की घोषणा कर चुके हैं। यानी, मासिक आमदनी होगी महज़ **4,628 रुपये**! **अच्छा होता कि नेताओं, नौकरशाहों, मैनेजरों को यह न्यूनतम मज़दूरी स्वीकार करने पर मजबूर किया जाता, जो वैसे भी कुछ नहीं करते और परजीवियों की तरह जनता का ख़ून चूस रहे हैं।** यह राशि आर्थिक सर्वेक्षण **2017** में सुझाये गये तथा सातवें वेतन आयोग द्वारा तय किये गये न्यूनतम मासिक आमदनी **18,000 रुपये** का एक-चौथाई मात्र है, हालाँकि आज रु. 18,000 भी एक इज्जत-आसूदगी की ज़िन्दगी जीने के लिए पर्याप्त मज़दूरी नहीं होगी। यही नहीं पन्द्रहवें राष्ट्रीय श्रम सम्मलेन (**1957**) की सिफ़ारिशों (जिसके अनुसार न्यूनतम मज़दूरी, खाना-कपड़ा-

मकान आदि बुनियादी ज़रूरतों के आधार पर तय होनी चाहिए) और सुप्रीम कोर्ट के **1992** के एक निर्णय की अनदेखी करते हुए कैलोरी की ज़रूरी खपत को **2700** की बजाय **2400** पर रखा है और तमाम बुनियादी चीज़ों की लागत भी **2012** की क़ीमतों के आधार पर तय की गयी है**! यानी मज़दूरों की मज़दूरी को कम-से-कम करने के लिए मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा सीधा फ़र्ज़ीवाड़ा और भ्रष्टाचार।** मोदी सरकार की इन्हीं नीतियों का नतीजा है कि मेहनतकश तबक़े की आय में कमी आयी है और महँगाई की मार उनपर पहले से ज़्यादा पड़ रही है।

आय में गिरावट और वस्तुओं के बढ़ते दाम का नतीजा है कि मेहनतकश तबक़े की थालियों से लगातार दालें व सब्ज़ियाँ गायब होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो द्वारा **2012** में किये गये आख़िरी सर्वे में बताया गया था कि **1979** की तुलना में **2012** में औसतन हर ग्रामीण को **550** कैलोरी उर्जा**, 13** ग्राम प्रोटीन**, 5** मिग्रा आयरन**, 250** मिग्रा कैल्शियम और **500** मि ग्रा विटामिन ए प्रतिदिन कम मिल रहा है। अब ऊपर दिये आँकड़ों से साफ़ अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि क़ीमतों के बढ़ने से ये आँकड़े पिछले **10** सालों में और भी अधिक भयानक हुए होंगे। एक बड़ी आबादी सिर्फ़ रोज़मर्रा के सामान जुटाने भर कमा रही है।

पूँजीपतियों को खुली छूट और रियायतें और जनता पर करों का बढ़ता बोझ!

महामारी से पहले**, 2019** में**,** केन्द्र सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स स्लैब को **30** प्रतिशत से घटाकर **22** प्रतिशत कर दिया था**,** जिसमें नयी निगमित कम्पनियाँ कम प्रतिशत (**15** प्रतिशत) का भुगतान कर रही थीं। इस नयी कराधान नीति के परिणामस्वरूप कुल **1.84** लाख करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ और इस वजह से **2019-20** में सरकार को कर राजस्व में संशोधन करने की ज़रूरत पड़ी। राजस्व बढ़ाने के लिए**,** केन्द्र सरकार द्वारा माल और सेवा कर (जीएसटी) में बढ़ोतरी की गयी और डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया। जीएसटी और ईंधन कर दोनों की अप्रत्यक्ष प्रकृति ने उन्हें प्रतिगामी बना दिया है**,** जिससे मेहनतकश आबादी पर बोझ बढ़ता गया। **18** जुलाई **2022** से मोदी सरकार ने खाने की बुनियादी चीज़ों पर पाँच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फ़ैसला किया। इसके बाद से **25 किलो/25 लीटर** से कम अनाज और तेल के दाम महँगे हो गये। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क

बोर्ड ने बताया है कि **25** किलो से कम सभी प्री पैकेज्ड फ़ूड पर पाँच प्रतिशत जीएसटी लगायी जायेगी। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगने के बाद मुख्यतः आटा, चावल, दाल, तेल, पनीर, दही जैसी चीज़ें महँगी हुई हैं।

जीएसटी के अलावा आमदनी के अनुसार प्रत्यक्ष कर में भी कटौती की जाती रही है और उसके बदले अप्रत्यक्ष करों को बढ़ाया जाता रहा है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर नीचे की **50 प्रतिशत** आबादी शीर्ष **10 प्रतिशत** की तुलना में, आय के प्रतिशत के रूप में, अप्रत्यक्ष कराधान पर छह गुना अधिक भुगतान करती है। तमाम खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं से एकत्र किए गये कुल कर का **64.3 प्रतिशत** नीचे के **50 प्रतिशत** आबादी से आ रहा है। कुल जीएसटी का दो-तिहाई से थोड़ा कम नीचे के **50 फ़ीसदी** आबादी से आ रहा है, अनुमान के मुताबिक मध्यम **40 फ़ीसदी** आबादी से एक-तिहाई और शीर्ष **10 फ़ीसदी** आबादी से सिर्फ़ तीन से चार फ़ीसदी आ रहा है। और इस बार के बजट में तो सरकार ने प्रत्यक्ष करों में कमी की है और पूँजीपति वर्ग और साथ ही उसके पिछलग्गू खाते–पीते मध्यवर्ग को लाभ पहुँचाया है। पहले आयकर के छह स्लैब्स थे जिन्हें घटाकर अब पाँच स्लैब कर दिया गया है। अब **रु. 3 लाख प्रति वर्ष** की आय तक कोई कर नहीं लगेगा, रु. **3** से **6 लाख** की आय वाले को **5 प्रतिशत** आयकर देना होगा, रु. **6** से **9 लाख प्रति वर्ष** वाले को **10 प्रतिशत,** रु. **9** से **12 लाख प्रति वर्ष** वाले को **15 प्रतिशत,** रु. **12** से **15 लाख प्रति वर्ष** वाले को **20 प्रतिशत** और रु. **15 लाख प्रति वर्ष** से अधिक वालों को **30 प्रतिशत** आयकर देना होगा। नयी आयकर व्यवस्था में आयकर में छूट की सीमा को रु. **5 लाख प्रति वर्ष** वालों से बढ़ाकर रु. **7 लाख प्रति वर्ष** तक कर दिया गया है, जिसे अपनाने वाले खाते-पीते मध्यवर्ग को साल में क़रीब रु. **34,000** रुपये का फ़ायदा होगा। **लेकिन मध्यम मध्य वर्ग को मिलने वाला यह फ़ायदा उस फ़ायदे के मुक़ाबले मामूली है जो कि उच्च वर्ग और उच्च मध्य वर्ग को मिलेगा।** अधिकतम आयकर दर को **42.7 प्रतिशत** से घटाकर **37** से **25 प्रतिशत** तक ला दिया गया है। **यानी, करों से मुक्ति सबसे ज़्यादा सबसे अमीर लोगों को दी गयी है, यानी पूँजीपति, बड़े व्यापारी, ऊँची तनख़्वाहें उठाने वाले पेशेवर आदि।**

यानी एक तरफ़ पूँजीपतियों को छूट और दूसरी तरफ़ जनता की लूट जारी है! *इण्डियन एक्सप्रेस* की एक रिपोर्ट के अनुसार **2020-21** में, कॉरपोरेट्स को प्रोत्साहन और कर छूट के रूप में सरकार का अनुमानित राजस्व **1,03,285.54 करोड़ रुपये** है। सरकारी व गैर सरकारी बैंकों ने जनता की गाढ़ी कमाई को अम्बानी-अडानी-टाटा-बिड़ला को ऋण के तौर पर दिया है। **मोदी राज में 2015 से 2021 तक 6 सालों के बीच 11 लाख 19 हजार करोड़ के ऋण बट्टे-खाते में डाल दिये गये जिसमें से मात्र एक लाख करोड़ की वसूली हुई है। यानी 10 लाख 19 हजार करोड़ रुपए धन्ना सेठों के द्वारा सीधे हजम कर लिए गये, जबकि 2004 से 2014 के 10 सालों में ऋण माफी की राशि 22 हज़ार करोड़ थी। 25 लाख रुपये से ज़्यादा का कर्ज़ लेकर ना चुकाने वाले 'विलफुल डिफॉल्टरों' की संख्या 15,000 पहुँच चुकी है। जनता का पैसा लूटकर क़रीब 40 धनपशु तो देश छोड़कर ही भाग गये और सरकार ने उन्हें जाने दिया!** एक तरफ़ तो पूँजीपतियों को सारी रियायत दी जा रही है परन्तु दूसरी तरफ़ यही रियायत की वसूली अप्रत्यक्ष करों को बढ़ाकर जनता से की जा रही है।

जनता को भरमाने के लिए यह तर्क गढ़ा जाता है कि अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर सरकार जनता के लिए काम करेगी। उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ, शिक्षा, रोज़गार जैसी चीज़ें मुहैया करायेगी। लेकिन मौजूदा हालात तो यह बताते हैं कि जनता से लूटा हुआ पैसा या तो पूँजीपतियों को अपनी पूँजी बढ़ाने के लिए दिया जाता है, जैसा कि हम ऊपर आँकड़ों से देख चुके हैं। नहीं तो जनहित के नाम पर हमारे देश के नेतागण इन पैसों को डकार जाते हैं! उलटे बजट में आम जनता के हिस्से कुछ भी नहीं बचता। जैसा कि इस बार के बजट में **'प्रधानमन्त्री ग़रीब कल्याण योजना' (पीएमजीकेवाई)** जिसके तहत 10 किलोग्राम मुफ़्त अनाज राशनकार्ड धारकों को देने का प्रावधान कोविड काल में मोदी सरकार ने किया था, उसे **जनवरी 2023 से घटाकर 5 किलोग्राम कर दिया गया।** ज्ञात हो कि 2013 से ही 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा' क़ानून के तहत सभी राशनकार्ड धारकों को रु. 3/किलो की दर से चावल और रु. 2/किलो की दर से गेहूँ दिया जा रहा था जिसे मोदी ने अपने कार्यकाल में मुफ़्त कर दिया था। यह **पूँजीपति वर्ग का ही दबाव था कि इस योजना को बन्द किया जाये क्योंकि यह व्यापक मज़दूर और मेहनतकश आबादी की ज़रूरतमन्दी को कम कर रही थी, उनके मोलभाव की क्षमता बढ़ा रही थी**

और नतीजतन मज़दूरी पर बढ़ने का दबाव पैदा कर सकती थी। इसलिए इस बजट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत फ़ण्ड को रु. 214 लाख करोड़ से घटाकर इस वर्ष 1.37 करोड़ कर दिया गया है। कुल खाद्य सब्सिडी को रु. 2.87 लाख करोड़ से रु. 1.97 लाख करोड़ कर दिया गया है।

हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह कोई "मुफ़्त" अनाज नहीं है और न ही यह मोदी सरकार का कोई एहसान है। जो मेहनतकश ग़रीब आबादी देश में सभी चीज़ों और सेवाओं का उत्पादन करती है, उसकी खाद्य सुरक्षा की गारण्टी लेना और उसे पर्याप्त और पोषणयुक्त भोजन मुहैया कराना सरकार की ज़िम्मेदारी है। इसके लिए भारी अप्रत्यक्ष करों के रूप में भी देश की जनता पहले ही आवश्यता से ज़्यादा क़ीमत चुका चुकी है। इसलिए हमारा मानना है कि अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जहाँ तक जनता की बुनियादी सुविधाओं की बात है, तो बड़े-बड़े पूँजीपतियों और धन्नासेठों पर अतिरिक्त कर लगाकर जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी की जानी चाहिए!

क्या आपको पता है कि अगर भारत के अरबपतियों की पूरी सम्पत्ति पर **2 फ़ीसदी की दर** से एक बार कर लगा दिया जाये तो इससे देश में अगले तीन साल तक कुपोषितों के पोषण के लिए **40,423** करोड़ रुपये की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष **10** सबसे अमीर लोगों की सम्पत्ति **27.52** लाख करोड़ है। क्या आपको पता है कि भारत के **100** सबसे अमीर लोगों की संयुक्त सम्पत्ति (**54.12** लाख करोड़ रुपये) के जरिये पूरे केन्द्रीय बजट को **18** महीने से अधिक समय तक निधि दिया जा सकता है।

ऐसे में हमारी यह मांग जायज़ है कि अप्रत्यक्ष करों को पूरी तरह खत्म किया जाये और उसके बदले सम्पत्ति के आधार पर प्रगतिशील प्रत्यक्ष करों की व्यवस्था को मज़बूत किया जाय। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार मोदी सरकार की इन्हीं जनविरोधी नीतियों का नतीजा रहा कि अमीरी-ग़रीबी की खाई पिछले 10 सालों में और गहरी होती गयी।

बढ़ती असमानता

मोदी सरकार की पूँजीपरस्त नीतियों का नतीजा था कि अमीरी-ग़रीबी की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। महँगाई की मार से ग़रीब और ग़रीब हो रहे हैं और अमीर और अमीर! कोरोना काल में तो जनता द्वारा स्वास्थ्य पर हुए ख़र्च और बेरोज़गारी के भयंकर आलम के कारण ग़रीबी और बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ़ इसी काल में पूँजीपतियों की सम्पत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई है। *ऑक्सफैम इण्डिया* की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष 1% आबादी के पास 2021 में कुल सम्पत्ति का 40.5% से अधिक हिस्सा था, जबकि नीचे के 50% या 700 मिलियन लोगों के पास कुल सम्पत्ति का लगभग 3% था। इसके अतिरिक्त, महामारी के दौरान अमीर और अमीर हो गये, और उनकी सम्पत्ति में वास्तविक रूप से 121%, या प्रति दिन 3,608 करोड़ रुपये की वृद्धि देखी गयी। हर पूँजीवादी संकट के दौरान यह होता है क्योंकि बड़ी पूँजी छोटी पूँजियों और छोटे माल उत्पादकों को निगलती जाती है। नतीजतन, संकट के दौर में कुल मूल्य उत्पादन घटता है, लेकिन सबसे अमीर वर्ग को फ़ायदा होता है, क्योंकि वह संकट की मार को झेल सकने में अक्षम छोटी पूँजी और सबसे ज़्यादा, छोटे माल उत्पादकों को निगल जाती है।

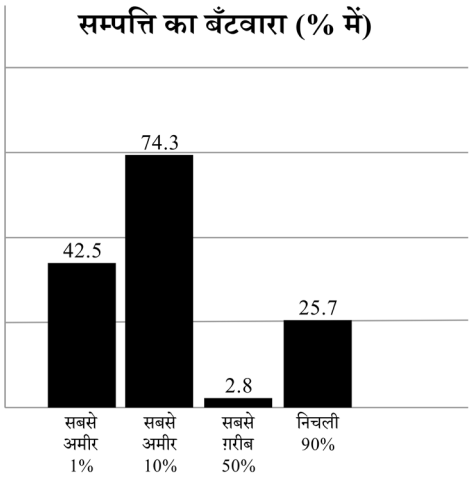

अभी हाल ही में *बिज़नस स्टैण्डर्ड* द्वारा यह रिपोर्ट आयी कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में दुगुने की वृद्धि हुई है। *बिज़नेस स्टैण्डर्ड* ने बताया कि 2014-15 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय (मौजूदा क़ीमतों पर) 86,647 रुपये थी। यह अब 172,000 रुपये है। यह 98.5% की वृद्धि है। सरकार द्वारा इसका ढिंढोरा हर जगह पीटा जा रहा है। लेकिन इसका

मतलब यह नहीं है कि पूरी जनसंख्या की आय में वृद्धि हुई है। **इसकी असल सच्चाई यह है कि आय में यह वृद्धि ऊपर की 10% आबादी की आय की वृद्धि है। इसके विपरीत, औसत वेतन गिर रहा है, और संभवतः वास्तविक रूप से और भी कम है। औसत आय से कभी यह नहीं पता चल सकता है कि देश में संसाधनों का बँटवारा कैसा है। जाहिर है, भारत के मेहनतकशों ने अपनी हाड़तोड़ मेहनत से देश की कुल आय में दोगुने की बढ़ोत्तरी की है, लेकिन वह सारी बढ़ोत्तरी सेठों-व्यापारियों की तिजोरी में गयी है।**

2012 और 2021 के बीच, भारत में निर्मित सम्पत्ति का 40 प्रतिशत केवल 1 प्रतिशत आबादी के पास गया है और केवल 3 प्रतिशत धन नीचे के 50 प्रतिशत तक गया है। भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 2020 में 102 से बढ़कर 2022 में 166 हो गयी है। गौतम अडानी भारत और एशिया का दूसरे सबसे धनी व्यक्ति और शायद पहला सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, जिसका भ्रष्टाचार मोदी जी से दोस्ती के कारण "राष्ट्रवाद" और "धर्मरक्षा" के "पवित्र-पावन" पर्दे से ढँक गया है! कोरोना काल यानी पिछले साल 2021 में इसकी सम्पत्ति में 49 अरब डॉलर का इज़ाफ़ा हुआ है। वहीं रिलायंस इण्डस्ट्रीज का प्रमुख मुकेश अम्बानी 103 अरब डॉलर की सम्पत्ति के साथ दूसरा सबसे अमीर भारतीय बना हुआ है। उसकी सम्पत्ति में सालाना आधार पर 24 फ़ीसदी की वृद्धि हुई है। *हुरुन ग्लोबल* की अमीरों की सूची के अनुसार पिछले 10 वर्षों में अम्बानी की सम्पत्ति 400 फ़ीसदी और अडानी की सम्पत्ति 1830 फ़ीसदी बढ़ी है।

इस बीच, भारत में ग़रीब आबादी जीवित रहने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को भी वहन करने में असमर्थ हैं। **भूखे भारतीयों की संख्या 2018 में 190 मिलियन से बढ़कर 2022 में 350 मिलियन हो गयी।** सर्वोच्च न्यायालय में केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, **2022 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 65 प्रतिशत मौतें भूख के कारण हुई हैं।** ऑक्सफैम का कहना है कि **भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा 228.9 मिलियन ग़रीब हैं।** अक्टूबर 2022 की वैश्विक भूख सूचकांक की रिपोर्ट में यह बताया गया है की भुखमरी के मामले में भारत दुनिया के 121 देशों में 107वें स्थान पर है और एशिया, अफ़्रीका, लैटिन अमेरिका के कई ग़रीब देशों से भी बुरी स्थिति भारत की है। आप मानें या न मानें, इन मामलों में तो मोदी जी ने भारत को "विश्वगुरू" बना ही दिया है! गर्व करिये!

नहीं करेंगे तो आप पर "राष्ट्रद्रोह" और "देशद्रोह" का मुक़दमा भी लगा सकती है मोदी जी की सरकारी एजेंसियाँ!

2019 में महामारी के बाद, नीचे की 50 प्रतिशत आबादी ने अपनी सम्पदा को छिनते हुए देखना जारी रखा है। 2020 तक, उनकी आय का हिस्सा गिरकर राष्ट्रीय आय का केवल 13 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था और उनके पास सम्पत्ति का 3 प्रतिशत से भी कम था। इसका प्रभाव असाधारण रूप से आहार में कमी, कर्ज़ में वृद्धि और मौतों में हुआ है। पर यदि यही स्थिति है, तो आख़िर में सवाल उठता है कि इसपर किया क्या जाये? हम जानते है कि यह सरकार हमें बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मुहैय्या कराती है, उलटे आम जनता को लूट कर अय्याशी की मीनारें खड़ी की जा रही हैं। हम यह भी जानते हैं कि महँगाई का असल कारण यह पूँजीवादी व्यवस्था है और इसके साथ ही मोदी सरकार की नीतियों के कारण महँगाई का कहर मेहनतकश जनता पर ज़्यादा बरपा हुआ है। **लेकिन सवाल अभी बना हुआ है कि आख़िर किया क्या जाये?**

अन्धकार है घना-पर संघर्ष है ठना!

साथियो, इस अन्धकार भरे साम्प्रदायिक हिटलरशाही के दौर में हमारे पास एकमात्र संघर्ष का रास्ता बचता है! यह कोई छोटा-मोटा अस्त्र नहीं है, बल्कि वह महाअस्त्र है जिसने इतिहास में बार-बार बड़े-बड़े तानाशाहों की सत्ताओं को ज़मींदोज़ कर दिया है, उनके तख़्त और ताज उछाल दिये हैं।

एक मुनाफ़ा केन्द्रित व्यवस्था में आम जनता को ग़रीबी, महँगाई और मुफ़लिसी के अलावा और कुछ नसीब नहीं हो सकता। हम जानते हैं की मुनाफ़ाकेन्द्रित पूँजीवादी व्यवस्था में महँगाई एक आम परिघटना है। वैसे तो तमाम पार्टियों की सरकारें पूँजीपति वर्ग की मैनेजिंग कमिटी का काम करती रही हैं। लेकिन मोदी सरकार ने पूँजीपति वर्ग की सेवा में पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और नंगे रूप में बड़ी पूँजी की सेवा में संलग्न रही। **मज़दूरों व मेहनतकश तबकों की सबसे बड़ी दुश्मन धन्नासेठों व अमीरज़ादों की वह सरकार होती है, जो जनता को धार्मिक कट्टरता फैलाकर बाँटती है, किसी अल्पसंख्यक आबादी को नक़ली दुश्मन बना डालती है, निम्न मध्यवर्ग की सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा का फ़ायदा उठाकर और उनमें इस**

नक़ली दुश्मन का नक़ली भय पैदाकर एक धार्मिक उन्माद पैदा करती है, दंगे करवाती है, जनता को बाँटती और राज करती है और "राष्ट्रवाद" और "धर्मध्वजारक्षा" की चदरिया के पीछे पूँजीपतियों की सेवा करती है। आज की मोदी सरकार की यही पहचानें हैं। जितनी जल्दी समझ जायें अच्छा होगा, वरना कल देर हो जायेगी।

आज इनकी पूँजीपरस्त नीतियों की वजह से ही अमीरी-ग़रीबी की खाई इतनी चौड़ी हो चुकी है। इनके द्वारा पूँजीपतियों को करो में छूट दी जाती है और उसकी वजह से होने वाले पूरे राजस्व घाटे का ख़र्च अप्रत्यक्ष करों के ज़रिये आम जनता की जेब से वसूला जाता रहा है। मुट्ठी भर पूँजीपतियों के मुनाफ़े के लिए पूरी जनता को बेरोज़गारी, ग़रीबी, महँगाई की खाई में धकेला जाता रहा है।

आम जन इस मुद्दे पर कोई सवाल ना उठा सकें इसलिए ही मोदी सरकार और संघ परिवार द्वारा जनता को धर्म-जाति-क्षेत्र-भाषा आदि में बाँटा जाता रहा है। **नक़ली मुद्दों जैसे लव जिहाद, गौ हत्या, मंदिर-मस्जिद, पाकिस्तान-चीन आदि में उलझा दिया जाता है। आप पूछेंगे कि ये नक़ली मसले कैसे हैं? आइये, देखते हैं।** अगर गाय को भाजपा 'माता' मानती है, तो वह गोवा, केरल और उत्तर-पूर्व में बीफ़ की आपूर्ति कम न होने देने के वायदे क्यों करती है? क्या गाय केवल उत्तर भारत में भाजपा की माता है? क्या गोरक्षा का ढोल बजाने वाला भाजपा का दंगाई नेता संगीत सोम *अल दुआ* नामक बूचड़खाने का एक निदेशक नहीं था? **नगालैण्ड के भाजपा नेता विसासोली ल्होंगू ने क्यों कहा कि नगालैण्ड में कभी बीफ़ बैन नहीं लगेगा? भाजपा नेता व मणिपुर के मुख्यमन्त्री बिरेन सिंह ने क्यों कहा कि मणिपुर में बीफ़ खाने पर कोई रोक नहीं, क्या खाना है यह सबका व्यक्तिगत मसला है?** बात तो सही है, खान-पान, पहनावा, रहन-सहन लोगों का व्यक्तिगत मसला है और इसमें किसी पार्टी या सरकार को दख़ल देने का कोई हक़ नहीं। फिर भाजपा यह दोमुँहापन क्यों दिखाती है? **मेघालय के भाजपा नेता अर्नेस्ट मावरी ने क्यों कहा कि "मैं बीफ़ खाता हूँ, यह मेघालय की जीवनशैली है और इसे कोई नहीं रोक सकता"? केरल में मलप्पुरम में उम्मीदवार भाजपा नेता श्रीप्रकाश ने क्यों वायदा किया था कि वहाँ वह बीफ़ की सप्लाई को कम नहीं होने देंगे और बीफ़ के उपभोग पर कभी रोक नहीं लगायी जायेगी? 2017 में ख़ुद अमित शाह ने क्यों कहा था कि गोवा में भाजपा का बीफ़ पर बैन**

लगाने का दूर-दूर तक कोई इरादा नहीं है? भाजपा के गुरू विनायक सावरकर ने तो कहा था कि गाय केवल एक पशु है, कोई माता नहीं! इस पर भाजपा का क्या कहना है? कुछ नहीं! क्यों? **वजह साफ़ है: गोरक्षा केवल बहाना है, जनता की एकता तोड़ना असली निशाना है।**

इसी प्रकार 'लव जिहाद' भी एक फ़र्ज़ी मसला है। अगर 'लव जिहाद' भाजपा को ख़तरा दिखता है, तो भाजपा शाहनवाज़ हुसैन की एक हिन्दू महिला से शादी, भाजपा नेता मुख़्तार अब्बास नक़वी की एक हिन्दू महिला से शादी, भाजपा नेता सुशील मोदी की एक इसाई महिला से शादी, भाजपा नेता सिकन्दर बख़्त की एक हिन्दू महिला से शादी, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी की एक मुसलमान से शादी 'लव जिहाद' क्यों नहीं है? 'लव जिहाद' क्या केवल बाकी जनता के लिए है ताकि वे इस बकवास पर अपना सिर-फुटौव्वल करे? वास्तव में, यह मसला भी फ़र्ज़ी है और जनता को बेवकूफ़ बनाकर बाँटने के लिए खड़ा किया गया है। किन्हीं भी दो वयस्कों को अपनी इच्छा से विवाह करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए और उसमें दख़ल देने का किसी को कोई हक़ नहीं होना चाहिए।

चीन को लेकर मोदी सरकार अन्धराष्ट्रवाद का हौव्वा खड़ा करती रहती है ताकि लोगों को एक नक़ली भय में फँसाकर यह भरोसा दिलाया जाय कि चीन ने हमला कर दिया तो मोदी जी ही निपट पायेंगे! इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता और यह डर ही एक नक़ली डर है। अगर मोदी जी को चीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की करनी है, तो उनको संघ परिवार की गुण्डा-वाहिनियों में इकट्ठा कुण्ठित चवन्नियों-अठन्नियों को समझाना चाहिए कि चीनी झालर, खिलौनों के बहिष्कार से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये खिलौने और झालर भारत के बाज़ार में मोदी सरकार की इच्छा के बिना नहीं आते! **अगर चीन के "ख़तरे" से मोदी जी निपटना ही चाहते हैं तो सबसे पहले मोदी सरकार को चीन से आयात-निर्यात पर पाबन्दी लगा देनी चाहिए, लेकिन जब चीन को इस प्रकार "लाल आँखें" दिखाने की बात आती है, तो मोदी जी की आँखों में काला मोतिया या रतौंधी छा जाती है!** हालत यह है कि अभी भारत के कुल आयात में अकेले चीन से होने वाले आयात का हिस्सा **16 प्रतिशत** पहुँच गया है,

जो तीन दशक पहले मात्र 5 प्रतिशत था और इसकी क़ीमत **90 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के क़रीब है! **कोई भी आयात देश में सरकार की इजाज़त के बिना नहीं होता।** तो मोदी सरकार चीनी आयात को बढ़ाती क्यों जा रही है? ऊपर से भारत का चीन को निर्यात केवल 23 बिलियन डॉलर था, यानी **67 बिलियन डॉलर (55,38,75,60,00,00 रुपये या 55.39 खरब रुपये) का व्यापार घाटा! यह मोदी जी क्या कर रहे हैं?** आप समझ ही गये होंगे कि चीन को लेकर अन्धराष्ट्रवाद की लहर फैलाना भी केवल संघ परिवार व मोदी सरकार के लिए जनता को एक उन्माद में बहाकर सत्ता में पहुँचने का हथकण्डा मात्र है। जहाँ तक चीनी साम्राज्यवाद के साथ वास्तव में सीमा विवाद का मसला है, वहाँ मोदी सरकार फुस्स पटाखा साबित हुई है। चीन के सामने मोदी जी दहाड़ने के लिए मुँह खोलते हैं लेकिन मुँह से 'म्याऊँ' निकल जाता है! **वास्तव में, चीन की जनता और भारत की जनता में कोई झगड़ा नहीं है।** वहाँ के सामाजिक फ़ासीवादी ताक़तों से जनता वैसे ही त्रस्त है, जैसे यहाँ के साम्प्रदायिक फ़ासीवादियों से जनता त्रस्त है। सरहदों के हर ओर "राष्ट्रवाद" की सिगड़ी इसलिए गर्माई जाती है, ताकि जनता को गुमराह कर अपने पीछे चलाया जा सके और जनता अपने वास्तविक मुद्दों व हितों को भूलकर फ़र्ज़ी मुद्दों में बह जाये। किसी ने सही कहा था, "राष्ट्रवाद उचक्कों की अन्तिम शरणस्थली है।" **देशप्रेमी होने का अर्थ किसी नेता, धर्म या पार्टी के प्रति वफ़ादारी नहीं होती, बल्कि देश के प्रति वफ़ादारी होती है। लेकिन देश कोई कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता, बल्कि उसमें रहने वाले वे मेहनतकश लोग होते हैं, जो हरेक चीज़ व सेवा का अपनी मेहनत से उत्पादन करते हैं। यदि किसी पार्टी की सरकार, कोई व्यवस्था व उसकी नीतियाँ इन मेहनतकशों के हक़ों को छीनती है, उन्हें रोज़गार नहीं देतीं, उन्हें महँगाई के बोझ तले दबा देती हैं, शिक्षा व चिकित्सा को बाज़ारू माल बना देती हैं, तो वे हैं देशद्रोही। नरेन्द्र मोदी, भाजपा, या संघ देश नहीं हैं, हम हैं देश, हम जो सारे कल-कारख़ानों, खेतों-खलिहानों, खानों-खदानों, दफ़्तरों में दिन भर खटते हैं, मरते हैं। इसलिए इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाना कोई देशद्रोह नहीं बल्कि देशप्रेम की निशानी है।**

इसलिए उन सारे मुद्दों को जब आप क़रीब से देखेंगे जिन पर संघ परिवार

और मोदी सरकार धार्मिक उन्माद, कट्टरता व अन्धराष्ट्रवाद फैलाते हैं, तो आप पायेंगे कि ये सारे ही एक विशाल फ़र्ज़ीवाड़ा, एक विराट घपला, घोटाला और सफेद झूठों का अम्बार हैं।

आज हमें संघ परिवार व भाजपा सरकार तथा उनकी गुण्डा-वाहिनियों की असलियत को समझने की ज़रूरत है। इनकी चालों को बेनक़ाब करने की ज़रूरत है। आज इन्ही मुद्दों की आड़ में हमसे हमारे बुनियादी अधिकार भी छीने जा रहे हैं और पूँजीपतियों के मुनाफ़े और नेता-मन्त्रियों-अफ़सरों की ऐय्याशी के लिए आम जनता के ख़ून-पसीने को बहाया जा रहा है। ऐसे में, चुपचाप तमाशबीन बन कर बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा।

इसके लिए आज यह ज़रूरत है कि जनता को उनके असली मुद्दों पर एकजुट किया जाये और साम्प्रदायिक और फिरकापरस्त ताक़तों का असली 'चाल-चरित्र-चेहरा' सामने लाया जाये । **भगतसिंह जन अधिकार यात्रा** की शुरुआत इसी बात को ध्यान में रख कर की गयी है। निश्चित तौर पर, हमारे जीवन की रोज़मर्रा की तक़लीफ़ों का स्थायी समाधान तभी हो सकता है, जब क्रान्तिकारी रास्ते से एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाय जिसका सपना **शहीदे आज़म भगतसिंह, चन्द्रशेखर आज़ाद, अशफ़ाकुल्ला, सुखदेव, राजगुरू, यतीन्द्रनाथ दास, बी.के. दत्त** जैसे मेधावी, वैज्ञानिक क्रान्तिकारियों ने देखा था। यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समूहों में संगठित उत्पादक वर्ग, यानी मज़दूर, मेहनतकश और ग़रीब किसान मिलकर सारे खेतों-खलिहानों, कल-कारख़ानों, खानों-खदानों के साझा मालिक हों, इनके इन समूहों या मेहनतकश पंचायतों का ढाँचा राष्ट्रीय मेहनतकश पंचायत तक जाता हो, निर्णय लेने का अधिकार उनके हाथों में हो, चुने गये प्रतिनिधियों को तत्काल वापस बुलाने का अधिकार उनके हाथों में हो, ये जनता के समूह ही देश के पैमाने पर मिलकर तय करें कि क्या पैदा करना है, कैसे पैदा करना और उसका वितरण व विनिमय कैसे करना है; एक ऐसी व्यवस्था जिसमें रोटी खाने का हक़ उसी को हो, जो उत्पादक व उत्पादन-सहायक काम करता हो; किसी को परजीवी के समान दूसरे की मेहनत पर ऐय्याशी का हक़ न हो। यानी, सिर्फ स्वराज्य नहीं, बल्कि लोकस्वराज्य, मेहनतकश जनता का

अपना राज्य। यह हमारा दूरगामी लक्ष्य है, लेकिन इसके लिए जनता को जागृत, गोलबन्द और एकजुट करने का पहला क़दम क्या है? हमारा तात्कालिक काम है कि हम अपने रोज़मर्रा के मुद्दों व ज़रूरतों पर मौजूदा सरकार को घेरें, उसे मजबूर करें कि वह हमारा हक़ हमें दे, या फिर गद्दी छोड़ दे। ये मुद्दे हैं: रोज़गार गारण्टी का कानूनी हक़, समान व निशुल्क शिक्षा का हक़, समान व निशुल्क चिकित्सा का हक़, सरकारी आवास व्यवस्था का हक़, और **महँगाई से मुक्ति।**

हमारी ज़िन्दगी के इन्हीं असल मुद्दों पर जागृत, गोलबन्द और संगठित होकर संघर्ष करने के वास्ते भगतसिंह जन अधिकार यात्रा की शुरुआत की गयी है। जिस प्रकार हर तरह के जातिवाद, धार्मिक कट्टरपन्थ, अन्धराष्ट्रवादी उन्माद के घटाटोप के खिलाफ़ हमारे शहीदों ने संघर्ष किया था, आज उसी संघर्ष को नये सिरे से संगठित करने की ज़रूरत है। यह यात्रा इसी संघर्ष का एक उद्घोष है। इस यात्रा में निम्नलिखित माँगों पर जनता को गोलबन्द व एकजुट करने का संकल्प लिया गया है।

हमारी माँगें

1) **सभी वस्तुओं व सेवाओं पर सभी अप्रत्यक्ष करों को तत्काल समाप्त किया जाये और प्रगतिशील कराधान तन्त्र के ज़रिये अमीर वर्गों पर कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी व उत्तराधिकार टैक्स के रूप में प्रत्यक्ष कर लगाकर सरकारी राजस्व एकत्र किया जाये।** यह क़ीमतों के स्तर को सीधे आधा कर देगा।

2) **महँगाई पर नियन्त्रण के लिए जमाख़ोरी, वायदा व्यापार (फ्यूचर्स ट्रेड) व सट्टेबाज़ी पर रोक लगाने के लिए सख्त क़ानून बनाया जाये जिसके तहत ये दण्डनीय अपराध घोषित किये जायें।**

3) **बुनियादी वस्तुओं व सेवाओं के वितरण की व्यवस्था का राष्ट्रीकरण किया जाये** और सरकार उसे पूर्णत: अपने हाथों में ले।

4) **खाद्यान्न की क़ीमतों को बढ़ाने वाले व धनी फार्मरों व पूँजीवादी ज़मीन्दारों के लिए बेशी मुनाफ़ा देने वाले लाभकारी मूल्य की व्यवस्था को समाप्त किया जाये। सरकारी ख़रीद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा औसत लाभ दर को सुनिश्चित करने वाली क़ीमत निर्धारित की जाये और इस ख़रीद की**

व्यवस्था तक ग़रीब व मँझोले किसानों की पहुँच को सुनिश्चित किया जाये।

5) **सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाकर सभी नागरिकों को भोजन मुहैया कराया जाये।**

यदि ये क़दम उठाये जायें तो महँगाई पर नियन्त्रण पाया जा सकता है और आम मेहनतकश जनता को भारी राहत मिल सकती है। हम आप सभी का आह्वान करते हैं कि हमारे साथ आयें, इस यात्रा से जुड़ें। आज ज़रूरत है इन माँगों पर व्यापक आबादी को संगठित कर जुझारू संघर्ष करने की। इसलिए ही इस यात्रा की शुरुआत की गयी है। याद रखें: जो लड़ता है, वही जीतता है। **हम सभी इन्साफ़पसन्द मज़दूर-मेहनतकश साथियों, छात्रों-नौजवानों और प्रगतिशील व जनपक्षधर नागरिकों से अपील करते हैं कि आप सभी इस यात्रा में शामिल हों और इसे व्यापक बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।**

अन्धकार का युग बीतेगा - जो लड़ेगा वो जीतेगा!
बिन हवा न पत्ता हिलता है - बिन लड़े न कुछ भी मिलता है!!